

## बदलते तकनीकी युग के साथ महिला सुरक्षा संबंधी वधियक में सुधार की आवश्यकता

### चर्चा में क्यों?

अक्सर देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर महिलाएँ (वर्षिकर महिला पत्रकार) सबसे अधिक दुरुव्यवहार का शिकार होती हैं। इन सबके लिये सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसलिये भी किया जाता है क्योंकि यहाँ बना अपनी पहचान बताए किसी को इंगति करते हुए कुछ भी कहना बहुत आसान होता है। यही कारण है कि अक्सर इंटरनेट के माध्यम से महिलाओं के साथ दुरुव्यवहार करने, उन्हें धमकाने और उनके खिलाफ नफरत भरे अभियानों का संचालन होता रहता है।

### आई.आर.डब्लू. एक्ट

- उल्लेखनीय है कि महिलाओं के साथ दुरुव्यवहार के संबंध में बना एक 31 वर्ष पुराना कानून आई.आर.डब्लू. एक्ट (Indecent Representation of Women (Prohibition) Act) 1986, इंटरनेट के माध्यम से महिलाओं पर होने वाले हमलों को रोकने में काफी हद तक अप्रभावी साबित हुआ है।
- हालाँकि इस अधिनियम को वजिजापनों या प्रकाशनों, लेखों, चर्चों, ऑकड़ों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं की अश्लील नुमाइंदगी को प्रतबंधित करने के लिये पारित किया गया था, परंतु इसकी समस्या यह है कि यह अधिनियम केवल प्रिंट मीडिया से ही संबंधित है।
- इस वधियक में महिलाओं के साथ किये जाने वाले 'अभद्र प्रतनिधित्व' को परभाषित किया गया है।

### कनि-कनि संशोधनों का प्रस्ताव रखा गया है?

- संशोधन वधियक के अंतर्गत 'अभद्र प्रतनिधित्व' के अंतर्गत महिलाओं के साथ अशुचित या अपमानजनक व्यवहार करना, उन्हें अपमानित करना अथवा ऐसी कोई हरकत करना जिससे महिलाओं का अपमान होता हो अथवा किसी भी प्रकार से उन्हें नुकसान पहुँचाना, उनके साथ बेईमानी करना तथा उनकी सार्वजनिक नैतिकता को कष्ट पहुँचाए जाने की संभावनाओं और स्थितियों को शामिल करने की सफारिश की गई है।
- यह वधियक 'वजिजापन' और 'वतिरण' की परभाषाओं में भी संशोधन करता है। साथ ही यह सामग्री के 'इलेक्ट्रॉनिक रूप' को भी परभाषित करता है।
- इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की ऐसी सामग्री के प्रकाशन या वतिरण को प्रतबंधित किया गया है, जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का अश्लील प्रतनिधित्व होता है।
- प्रस्तावित कानून के अंतर्गत अधिकतम कारावास में दो साल से तीन साल तक की बढ़ोतरी और कम से कम 2,000 रुपए से 50,000 रुपए तक के जुर्माने की बात कही गई है, जिससे पहले अपराध के मामले में 1 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है।
- उत्तरगामी अपराध के मामले में पाँच से सात साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक के जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
- इसके अतिरिक्त इस वधियक में उक्त मामलों की जाँच हेतु कम से कम नरीक्षक पद के एक पुलिस अधिकारी को नियुक्त किये जाने की भी बात कही गई है।

### अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता क्यों है?

- वर्ष 2012 में इस अधिनियम को संशोधन करने हेतु एक संशोधन वधियक संसद में पेश किया गया था, जो अभी तक लंबित है।
- इस अधिनियम में संशोधन हेतु पेश की गई सफारिशों में यह कहा गया है कि तकनीकी क्रांति के परिणामस्वरूप संचार के नए-नए रूपों का विकास हुआ है। उदाहरण के तौर पर, इंटरनेट और उपग्रह आधारित संचार, मल्टी-मीडिया जैसे जगि, केबल टेलीविज़न, इत्यादि।
- यही कारण है कि बदलते समय के साथ-साथ इस अधिनियम के दायरे को वसितृत करना बहुत आवश्यक हो गया है। नए संशोधनों के अंतर्गत मीडिया के उपरोक्त सभी रूपों को कवर किया जाना चाहिये।

### इस संबंध में सरकार का मत क्या है?

- सरकार भी यह मानती है कि इस कानून को पहले की अपेक्षा और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिये। साथ ही इसके अंतर्गत कठोर दंड की व्यवस्था भी की जानी चाहिये।
- साथ ही यह भी महसूस किया गया है कि यदि किसी भी परसिर में प्रवेश करने तथा किसी भी सामग्री की खोज और ज़बती करने की शक्त के संबंध में ऐसा प्रतीत होता है कि इससे अधिनियम में नहिंति प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है या फिर इन गतिविधियों को अधिनियम के तहत अपराध के रूप में इंगति किया गया है, तो इस संबंध में अधिक से अधिक प्रभावी कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- भवषिय में इस प्रकार की किसी भी खोज को प्रतबंधित करने के लिये इस संबंध में मज़बूत व्यवस्था की जानी चाहिये।

